



61

समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

विविध

/16 जवलपुर

विविध- 9037-I-16

श्री अमर सिंह गोंड आयु 52 वर्ष पिता श्री
रतीराम गोंड निवासी -29, ग्राम टीगन थाना
बरगी तहसील व जिला जवलपुर म.प्र

.....आवेदक

विरुद्ध

1. श्री कोशिक शर्मा पिता श्री विष्णु प्रसाद
शर्मा निवासी सिद्धेश्वर मंदिर के पास गंगा
नगर, गढा जवलपुर म.प्र।
2. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जवलपुर म.प्र

दिनांक 28-7-16 को
श्री सुनील सिंह जादौन
का. 570 जवलपुर
28-7-16

आवेदन पत्र वास्ते म.प्र भू-राज्य संहिता 1959 की धारा 32 के तहत

श्रीमान जी,

आवेदक की ओर से आवेदनपत्र निम्नानुसार है। :-

1. यहकि, आवेदक द्वारा अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर जवलपुर के प्रकरण क
116/अ-21/14-15 मे पारित आदेश दिनांक 06.06.2016 के विरुद्ध निगरानी
2196/एक/2016 प्रस्तुत की गई जिसमे दिनांक 22.7.2016 से निगरानी स्वीकार
की जाकर विक्रय की अनुमति प्रदान की गई ।
2. यहकि, श्रीमान महोदय द्वारा निगरानी 2196/एक/2016 मे पारित आदेश
दिनांक 22.7.2016 से निगरानी स्वीकार की जाकर विक्रय की अनुमति प्रदान की
गई परन्तु त्रुटिपूर्ण आदेश में खसरा नंबर 77/2 अंकित हो गया है जिसे 77/1
सुधार किया जाकर पढा जाना न्याय संगत है।
3. यहकि, श्रीमान न्यायालय के आदेश में टाइटल नेम मे निगरानी क
2195/एक/2016 अंकित हो गया है। जो कि निगरानी क 2196/एक/2016 है
जिसे सुधार किया जाना न्याय संगत है। एवं आदेश भी स्कैन होने पर दुसरे
प्रकरण के पेज संलग्न हो गये है जिसे भी न्याय हित में सुधार किया जाना
न्याय संगत है। अंतः निम्न संशोधन किया जाना न्याय संगत है-
 1. आदेश दिनांक 22-7-2016 के प्रत्येक पृष्ठ के टोप पर निगरानी क
2195/एक/2016 अंकित हो गया है जिसे सुधार कर प्रत्येक पृष्ठ पर
निगरानी क 2196/एक/2016 अंकित किया जाना न्याय संगत है।
 2. आदेश 22.7.16 के पैरा 2, पैरा 4 एवं पैरा 5 में भूमि खसरा नं 77/2 अंकित
हो गया है जिसे सुधार कर भूमि खसरा नं. 77/1 सुधार किया जाना न्याय
संगत है ।
4. यहकि, उक्त प्रकरण में आदेश दूसरे प्रकरण का संलग्न हो गया है जिसे सही सुधार कर
सही आदेश संलग्न किया जाना न्याय संगत है।
5. यहकि, अन्यु विन्दु सुनवाई के समय उठावे जावेगे।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर संशोधन
किया जाना न्याय संगत है। अन्य सुविधा जो न्याय संगत हो कृप्या प्रदान करें।

दिनांक

27.7.16

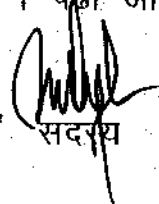
आवेदक
अमर सिंह गोंड
द्वारा अभिभाषक सुनील सिंह जादौन
एडवोकेट

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

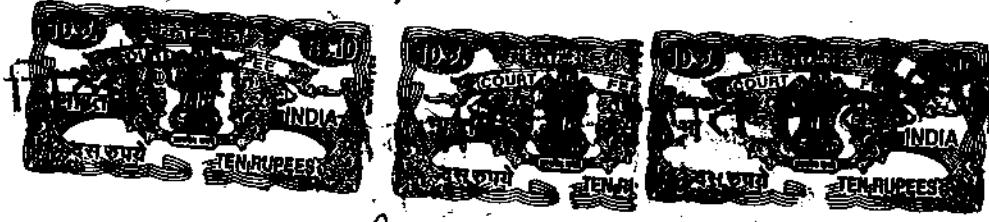
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

1877 नं. क्रमांक विविध 9037-एक/16

जिला -जबलपुर

दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश
1.8.16	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन द्वारा आवेदन पत्र वास्तु म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि निगरानी प्रकरण क्रमांक 2196-एक/16 के स्थान 2195-एक/16 प्रत्येक पेज पर अंकित हो गया है। उनके द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि आदेश दिनांक 22.7.16 के पैरा 2 पैरा 4 एवं पैरा 5 में भूमि खसरा न0 77/2 अंकित हो गया है जिसे सुधार कर 77/1 किया जावे।</p> <p>2- आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा निगरानी प्रकरण क्रमांक 2195-एक/16 के स्थान पर निगरानी 2196-एक/16 प्रत्येक पेज पर पढ़ा जावे। तथा पैरा 2, पैरा 4 एवं पैरा 5 में भूमि खसरा न0 77/2 के स्थान पर 77/1 पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका मूल आदेश का अंग माना जावेगी।</p> <p>श्रील आदेश श्री सुनील सिंह जादौन  सदस्य</p>

Handwritten mark



न्यायालय पीठासीन न्यायाधीश राजस्व मण्डल ग्वालियर संभाग ग्वालियर (म.प्र.)

राजस्व पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 116/अ-21/2015-16

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक - श्री अमर सिंह गौड़ उम्र 52 वर्ष पिता श्री रतीराम गौड़
निवासी- 29, ग्राम टीगन थाना बरगी तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.)
Adhar No. 2190 1591 0336

विरुद्ध

उत्तरवादी/अनावेदक - (1) श्री कौशिक शर्मा उम्र 38 वर्ष पिता श्री विष्णु प्रसाद शर्मा
निवासी- सिद्धेश्वर मंदिर के पास, गंगा नगर, गढ़ा, जबलपुर (म.प्र.)
Adhar No. 8042 8478 8661
(2) मध्यप्रदेश शासन

श्री अमर सिंह गौड़ (MS) का
हास बाज दि 4-7-16 को
परस्तुत

कलक जाक कोड
गजबलपुर मण्डल म.प्र. शासित

रिविजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

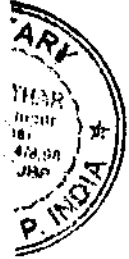
पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक निम्नलिखित निवेदन करता है कि :-

आवेदक द्वारा प्रस्तुत रिविजन राजस्व प्रकरण क्रमांक 116/अ-21/2015-16 अमर सिंह गौड़ विरुद्ध श्री कौशिक शर्मा ने माननीय कलेक्टर महोदय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.06.2016 से व्यथित होकर वर्णित तथ्यों एवं ग्राउंड के आधार पर प्रस्तुत की गई है।

रिविजन के तथ्य

1. यह कि रिविजनकर्ता आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है तथा ग्राम पिंडरई प.ह.नं. 36/28 रा.नि.मं. जबलपुर-2 तहसील व जिला जबलपुर जिसका खसरा नंबर 77/2 रकबा 0.400 हैक्टे. (एक एकड़) भूमि सिंचित/असिंचित भूमि के मालिक काबिज स्वामी है तथा तथा शासकीय अभिलेखों में उपरोक्त भूमि आवेदक के नाम पर दर्ज है।
2. यह कि आवेदक द्वारा अपनी उपरोक्त काश्तकारी भूमि विक्रय करने का अनुबंध पत्र अनावेदक क्र. 1 एवं 2 के मध्य दिनांक 20.08.2015 को किया था एवं उक्त भूमि के विक्रय करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा एक आवेदन धारा 165 (6) सहपठित खंड 2 म.प्र. भू.रा.संहिता के अंतर्गत माननीय जिलाध्यक्ष महोदय जबलपुर के समक्ष दिनांक 01.02.2016 को प्रस्तुत किया था। जिसका प्रकरण क्रमांक 116/अ-21/2015-16 था। उक्त आवेदन पर दिनांक 24.05.2016 को तर्क सुनने के पश्चात दिनांक 06.06.2016 को प्रकरण आदेश हेतु नियत किया जाकर दिनांक 06.06.2016 को आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया गया।
3. यह कि पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक विक्रय की गई भूमि के अतिरिक्त ग्राम टीगन प.ह.नं. 40 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर जिसका खसरा नंबर 126 रकबा 1.960 हैक्टे., खसरा नंबर 279 रकबा 0.250 हैक्टे., खसरा नंबर 285 रकबा 2.340 हैक्टे., खसरा नंबर 422 रकबा 0.160 हैक्टे., खसरा नंबर 396 रकबा 0.430 हैक्टे., इस प्रकार कुल रकबा 5.14 हैक्टे. याने बारह एकड़ पचासी डिसमिल भूमि सिंचित/असिंचित भूमि शेष बच रही है जिसका आवेदक पूर्ण मालिक स्वामी होकर काबिज है। शासकीय अभिलेखों में उक्त भूमि आवेदक के नाम पर दर्ज है।

2016



P
d/c

अमर सिंह गौड़

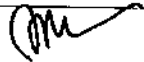
राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2195/1/2016

जिला-जवलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि. एवं आवेदक के हस्ताक्षर
२२.७.१६	<p>यह निगरानी कलेक्टर जवलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 116/अ-21/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 06-06-2016 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू- राज्य संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक ने कलेक्टर जवलपुर को आवेदन पत्र देकर अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम पिंडरई प.ह.नं. 36/28 रा.नि.मं. जवलपुर -2 तहसील व जिला जवलपुर में स्थिति भूमि खरारा नं 77/2 रकवा 0.400 है 0 उबड़ -खाबड़ होने एवं अन -उपजाऊ होने से भूमि को विक्रय कर शेष बच रही भूमि की उन्नती एवं बैंक का लोन चुकता करने हेतु भूमि को विक्रय किये जाने की अनुमति मांगी। कलेक्टर जवलपुर प्रकरण क्र 116/अ-21/2014-15 पंजीबद्ध किया तथा आवेदक के आवेदन में अंकित तथ्यों की जाँच कराकर आदेश दिनांक 06.06.2016 पारित किया एवं आवेदक का आवेदन अस्वीकार कर प्रकरण खारिज कर दिया इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।</p> <p>3- निगरानी मेमो में दर्शाए बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया ।</p>	





4- आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि आवेदक ने उसके निजी स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 77/2 रकबा 0.400 हे. के विक्रय की अनुमति इस आधार पर मांगी है कि उसके पास विक्रय की जाने वाली भूमि के अतिरिक्त ग्राम टीगंन प.ह.न.40 एवं ग्राम चनेरी प.ह.न. 39 में कुल 5.14 हे. भूमि शेष बच रही है। जिसके कारण विक्रय की जाने वाली भूमि के विक्रय उपरांत वह भूमिहीन नहीं होगा एवं भूमि विक्रय से प्राप्त धन से बच रही भूमि को उन्नत बनायेगा इसलिये भूमि विक्रय का प्रयोजन भी सम्भावना पर आधारित है जिसके कारण विक्रय अनुमति दिये जाने में बैधानिक अडचन नजर नहीं आती है। वैसे भी आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है आवेदक द्वारा संहिता की धारा 165 के प्रावधानों के कारण भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है, एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की बैधानिक अडचन नहीं है।

(1) आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादा विरुद्ध म0प्र0राज्य तथा एक अन्य 2013 रा0नि0-08-माननीय उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत है कि -

(1) भू-राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)-धारा 165(7-ख) तथा 158 (3) का लागू होना - उपबंधों के अंतःस्थापन से पूर्व पट्टा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये - बिना अनुमति के भूमि का अंतरण - उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया - उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया - उपबंध आकर्षित नहीं होते - भूमिस्वामी का अंतरण का अधिकार निहित अधिकार है।

(2) विधि का निर्वचन - का सिद्धांत - नवीन उपबंध का अंतःस्थापन

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

—भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया —ऐसे उपबंधकी भूतलक्षी प्रभावी होने की उपधारणा नहीं की जा सकती।

(2)दयाली तथा एक अन्य विरुद्ध महिला श्यामबाई 2004रा0नि0183में व्यवस्था की गई है कि भू-राजस्व संहिता 1959(म0प्र0)—धारा 165(7-ख) सरकारी पट्टेदार द्वारा आबंटन के 10 वर्ष पश्चात भूमिस्वामी अधिकार अर्जित किये —भूमि का विक्रय कर सकता है — कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा आवश्यक नहीं है।

5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जवलपुर द्वारा प्रकरण क 116/अ-21/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 06.06.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं निगरानी स्वीकार की जाकर आवेदक को ग्रम पिंडरई प.ह.नं. 36/28 रा.नि.मं. जवलपुर -2 तहसील व जिला जवलपुर में स्थिति भूमि खसरा नं 77/2 रकबा 0.400 हे0 के विक्रय की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:—

1—भूमि का कय-विक्रय के दस्तावेज का पंजीयन इस आदेश के तीन माह की अवधि के भीतर करना अनिवार्य है।

2—भूमि का कय -विक्रय पंजीयन दिनांक को प्रचलित गार्ड लाईन के मान से किया जावेगा।

3—केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी।




सर्वस्य